

26/6/86



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 1986 (वैशाख 27, 1908)
No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 1986 (VAISAKHA 27, 1908)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

प्रधान कार्यालय

पटियाला-147001, दिनांक 30 अप्रैल 1986

सूचना

क्रमांक पी० ई० आर०/4869--1. श्री के० आर० अली, अधिकारी म० प्र० ग्रे० श्री०-II, का स्थानान्तरण आंचलिक कार्यालय, चण्डीगढ़ से महाप्रबन्धक (परिचालन) सचिवालय, प्रधान कार्यालय पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 18-2-86 को कार्यग्रहण किया।

2. श्री एम० डी० सिंह, अधिकारी व० प्र० ग्रे० श्री०-IV का स्थानान्तरण पटियाला (माल रोड) शाखा से निरीक्षण विभाग में शाखा निरीक्षक के तौर पर किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 1-2-86 को कार्यग्रहण किया।

3. श्री बी० चतुर्वेदी अधिकारी, म० प्र० ग्रे० श्री०-II का स्थानान्तरण क्षेत्रीय प्रबन्धक-II पटियाला से संगठनात्मक आयोजना विभाग में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 10-1-86 को कार्यग्रहण किया।

4. श्री आर० के० नागिया, अधिकारी म० प्र० ग्रे० श्री०-II का स्थानान्तरण कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र चण्डीगढ़ से मानव संसाधन विकास विभाग प्रधान कार्यालय में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 29-1-86 को कार्यग्रहण किया।

5. श्री रविन्द्र कुमार शर्मा, अधिकारी म० प्र० ग्रे० श्री०-II का स्थानान्तरण नई दिल्ली (माडल बस्ती) में श्री० एण्ड एम० विभाग, प्रधान कार्यालय पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 21-1-86 को कार्यग्रहण किया।

6. श्री इन्द्रजीत सिंह, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्री०-I का स्थानान्तरण क्षेत्र-I (पटियाला) से एन० आई० बी० (विभाग) प्रधान कार्यालय पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 15-3-86 को कार्यग्रहण किया।

7. श्री एम० के० गुप्ता, अधिकारी व० प्र० ग्रे० श्री०-IV का स्थानान्तरण क्षेत्र प्र०-I (जालंधर) से एन० आई० बी० विभाग, प्रधान कार्यालय, पटियाला में विभागीय प्रबन्धक के तौर पर किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 10-3-86 को कार्यग्रहण किया।

8. श्री सोम नाथ अरोड़ा, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्री०-I का स्थानान्तरण धर्मोद से अग्रणी बैंक विभाग में सहयोगी अग्रणी बैंक अधिकारी संगरूर के तौर पर किया गया तथा उन्होंने वहाँ पर 31-3-86 को कार्यग्रहण किया।

9. श्री बी० एल० शर्मा, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्री०-I का स्थानान्तरण पटियाला (डी० सी० इन्ड्यू०) शाखा में तुलन-पत्र एवं सरकारी लेखा अनुभाग में किया गया तथा उन्होंने वहाँ पर 3-3-86 को कार्यग्रहण किया।

10. श्री वी० के० अग्रवान, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्रे०-I का स्थानान्तरण क्षेत्र प्र०-II (चण्डीगढ़) से ऋण मूल्यंकन विभाग, प्रधान कार्यालय पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 17-3-86 को कार्यग्रहण किया।

11. श्री एच० एम० आनन्द, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्रे०-I का स्थानान्तरण सी० आई० एण्ड आई० बी० विभाग से ऋण मूल्यंकन विभाग, प्रधान कार्यालय पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 10-3-86 को कार्यग्रहण किया।

12. श्री भागू राम गोयल, अधिकारी म० प्र० ग्रे० श्रे०-II का स्थानान्तरण निरीक्षण विभाग से वैकिक परिचायन विभाग, प्रधान कार्यालय, पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 4-3-86 को कार्यग्रहण किया।

13. श्री वी० के० गुप्ता, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्रे०-I का स्थानान्तरण बालका शाखा से भविष्य निधि अनुभाग, प्रधान कार्यालय, पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 31-3-86 को कार्यग्रहण किया।

14. श्री एम० एच० गुप्ता, अधिकारी क० प्र० ग्रे० श्रे०-I का स्थानान्तरण मैसूरखाना शाखा से केन्द्रीय लेखा अनुभाग, प्रधान कार्यालय, पटियाला में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 7-2-86 को कार्यग्रहण किया।

15. श्री एच० सी० विगवा, अधिकारी म० प्र० ग्रे० श्रे०-III का स्थानान्तरण पटियाला (माल रोड़) शाखा से कार्यकारी प्रशिक्षण केन्द्र पटियाला में मुख्य प्रशिक्षक के तौर पर किया गया है, उन्होंने वहाँ पर 29-1-86 को कार्यग्रहण किया।

16. श्री आर० एम० एटब्रस, अधिकारी म० प्र० ग्रे० श्रे०-II का स्थानान्तरण पटियाला (श्री० क्षेत्र) शाखा से कृषि विभाग, प्रधान कार्यालय में किया गया है तथा उन्होंने वहाँ पर 3-1-86 को कार्यग्रहण किया।

एन० जॉ० सरदाता, महाप्रबन्धक
(परिवर्तन)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक

सं० एन०-15/13/7/12/82-यो० एवं० वि०--कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 46(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत में महानिदेशक ने 16-4-86 ऐसी तारीख निश्चित की है जिसमें उक्त विनियम 95-क तथा कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा (विक्रित हितलाभ) नियम, 1958 में निदिष्ट चिकित्सा हितलाभ कर्नाटक राज्य के

निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमाता व्यक्तियों के परिवारों पर लागू होंगे, यानी:-

| राजस्व ग्राम का नाम हुबन्नी | तालुका | जिला |
|--------------------------------|---------|----------------|
| 1. अराकेरी ग्राम | बेगूर | दक्षिणी बंगलौर |
| 2. बोम्मानाहाली | बेगूर | दक्षिणी बंगलौर |
| 3. कोताप्पाता अप्राहारी पंचायत | बेगूर | दक्षिणी बंगलौर |
| 4. होंगापन्दरा | बेगूर | दक्षिणी बंगलौर |
| 5. मासान्ना | अतीबेले | अनोकल |
| 6. मदीवाला | बेगूर | बंगलौर |
| 7. हेबागोडी | अतीबेले | अनोकल बंगलौर |
| 8. कुदलु | सरजापुर | अनोकल बंगलौर |

एम० सुब्बा राव
निदेशक (योगता एवं विज्ञान)

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1986

सं० 28-आर० सी० (2)/23/86--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1964 के रेगुलेशन 133(1) के अनुसरण में दि कॉमिन आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को 3 अप्रैल, 1986 में पांडिचेरी में दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद् की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रार्थना है।

यह शाखा दक्षिण भारत क्षेत्रीय परिषद् की पांडिचेरी शाखा मानी जाएगी।

रेगुलेशन 133(3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है यह शाखा क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं निदेशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किए जाएंगे।

सं० 28-आर० सी० (1)/12/86--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1964 के रेगुलेशन 133(1) के अनुसरण में दि कॉमिन आफ दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया को 3 अप्रैल, 1986 में आनन्द में पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद् की शाखा स्थापित करने की सूचना देते हुए प्रार्थना है।

यह शाखा पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद् की अल्पद शाखा मानी जाएगी।

रेगुलेशन 136(3) के अन्तर्गत जैसा कि निर्धारित है यह शाखा क्षेत्रीय परिषद् के माध्यम से पश्चिद के नियंत्रण पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में कार्य करेगी और सभी उन निर्देशों का पालन करेगी जो कि परिषद् द्वारा समस्त-समय पर जारी किये जायेंगे।

दि इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल, 1986

सं० 1-सं० ए (13)/82:—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का अधिनियम) की धारा 30 उपधारा (1) और (3) के अधीन प्रदान अधिकारों का उपयोग करते हुए, इन्स्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की परिषद् ने चार्टर्ड रेगुलेशन 1964 में निम्नलिखित संशोधन किया है, इन संशोधनों को पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त धारा की उपधारा (3) के अनुसार अनुमोदित किया जा चुका है।

कथित रेगुलेशन में अनुसूची "बी" में पैराग्राफ 10 के बाह्य निम्नलिखित तथा पैराग्राफ "ए10 ए" जोड़ में यथा:—

10 ए अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये अपेक्षाये

(1) अन्तिम परीक्षा के लिये कोई भी प्रत्याशी सामान्य रूप से परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा, यदि वह पैराग्राफ 10 के उप पैराग्राफ (1) के अधीन दोनों ही ग्रुपों को या तो साथ साथ या अलग अलग परीक्षाओं द्वारा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रत्येक ग्रुप में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर तथा प्रत्येक ग्रुप के सभी प्रश्न पत्रों में कुल अंकों का न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है।

(2) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) में वर्णित अन्य बातों के होने पर भी किन्तु प्रत्याशियों ने ग्रुपों की कोई एक, किन्तु दोनों नहीं, परीक्षा अन्तिम परीक्षा में इस अनुसूची के अन्तर्गत जो 1 अक्टूबर 1986 से पूर्व की गई थी, उस छूट के अन्तर्गत जो 1 अक्टूबर, 1986 से पूर्व की गई थी, उस छूट के लिये ग्राह्य होगा जिसका उल्लेख नीचे की गई तालिका के कालम (2) में किया गया है, जैसा भी उनके मामले में ग्राह्य होगा तथा उसे अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा यदि वह शेष प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में वह अंक प्राप्त कर ले जिसका उल्लेख उपर्युक्त तालिका के कालम (3) में किया गया है।

उपरिलिखित तालिका इस प्रकार है:

1 अक्टूबर, 1986 से पूर्व यह छूट जिसके लिये यहां निर्दिष्ट कालम (2) की गई इस अनुसूची में अन्त- प्रत्याशियों 1 अक्टूबर, से परवर्ती परीक्षा अन्त- गंत अन्तिम परीक्षा में प्रत्याशियों 1986 के उपर्युक्त अनु- प्रश्नपत्रों में प्रत्याशियों को द्वारा उत्तीर्ण कि सवे ग्रुप सूची "बी" के अन्त- छूट प्राप्त नहीं है, का विवरण गंत लाई गई किसी भी प्रत्याशियों द्वारा अपेक्षित अन्तिम परीक्षा में ग्राह्य प्राप्त अंक है।

| 1 | 2 | 3 |
|--------------|--|---|
| केवल ग्रुप 1 | ग्रुप 1 के प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 तथा ग्रुप 2 के पत्र | (1) ग्रुप 1 के प्रश्न पत्र 4 से 40 प्रतिशत से |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---------------|---------------|
| | प्रश्न पत्र 5 | करा अंक नहीं। |

केवल ग्रुप 2

ग्रुप 1 का प्रश्न पत्र 4

(ii) ग्रुप 2 के प्रश्न पत्र 6, 7 और 8 में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं होने चाहिये और प्रश्न पत्र 6, 7 और 8 के कुल योग का 50 प्रतिशत से कम नहीं।

(1) ग्रुप 1 के प्रत्येक प्रश्न पत्र 1, 2 तथा 3 में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं तथा उपर्युक्त प्रश्न पत्र 1, 2 तथा 3 के कुल अंकों का 50 प्रतिशत से कम नहीं तथा,

(2) ग्रुप 2 के प्रश्न-पत्र 5, 6, 7 व 8 के प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत से कम अंक नहीं तथा उपर्युक्त प्रश्न पत्र 5, 6, 7 व 8 के कुल अंकों का 50 प्रतिशत से कम नहीं।

(3) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) में वर्णित अन्य बातों के होने हुए भी कोई प्रत्याशी ग्रुप के एक प्रश्न पत्र से अंकित हो जाता है परन्तु वह ग्रुप के शेष प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो वह उस ग्रुप में उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा, यदि वह उप प्रश्न पत्र जिसमें वह अस्फल हुआ है, सफल होने वाली आगामी गंत निम्नलिखित परीक्षाओं के किसी भी एक या अधिक परीक्षा में बैठता है तथा उस प्रश्न पत्र से न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है।

(4) उपर्युक्त उप पैराग्राफ (1) में वर्णित अन्य बातों के होने हुए भी यदि प्रत्याशियों जो उप पैराग्राफ (3) में नहीं आता हो और ग्रुप में एक या अधिक प्रश्नपत्रों में असफल हो जाता है किन्तु वह उस ग्रुप के किसी भी एक या अधिक प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तथा उस ग्रुप के शेष प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है तो वह उस प्रश्नपत्रों जिसमें उसने 60 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त किये हैं, सफल होने वाली आगामी गंत निम्नलिखित परीक्षाओं के किसी भी एक या अधिक प्रश्न पत्रों में प्रविष्टि के लिये ग्राह्य होगा तथा उसे उस ग्रुप में उत्तीर्ण घोषित समझा जायेगा यदि वह एक ही बार में ऐसे प्रत्येक प्रश्न पत्रों में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक तथा उसा ग्रुप के सभी प्रश्नपत्रों में, उस प्रश्न पत्र या उन प्रश्नपत्रों में जिनमें पहले की उपरिलिखित परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं, न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर ले।

(5) यहां उप पैराग्राफ (3) या उप पैराग्राफ (4) के उद्देश्य के लिये पैराग्राफ 10 के उप पैराग्राफ (1) के अन्तर्गत की गई अन्तिम परीक्षा में प्रत्याशियों द्वारा प्रश्न पत्र या प्रश्न पत्रों में की गई छूट अनुसूची बी की पैराग्राफ 9 के उप पैराग्राफ

(2) के अन्तर्गत अन्तिम परीक्षा के सम्बन्ध में भी लागू रहेंगे।

स्पष्टीकरण

इस उप पैराग्राफ के उद्देश्य के लिये, यहाँ वर्णित के अनुसार वह प्रश्नपत्र जिसमें प्रत्येकी अनुसूची बी बी के पैराग्राफ 9 के सब पैराग्राफ (2) के अधीन ली गई अन्तिम परीक्षा के सम्बन्ध में प्रवेश लेना चाहता है, का आशय ऐसी परीक्षा में उस प्रश्नपत्र से है जिसमें भाव के प्रश्नपत्र जिनका उल्लेख नोके किया गया है, तथा इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट किये गये 50 प्रतिशत के जोड़ने के उद्देश्य के लिये ग्रुप का आशय उस ग्रुप से है, जिसके अन्तर्गत उपर्युक्त भाव के प्रश्नपत्र आते हैं:—

इस अनुसूची के अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 86 अनुसूची "बीबी" के अधीन 1 अक्टूबर से पूर्व ली गई अन्तिम परीक्षा के प्रश्न 1980 के भाव ली गई अन्तिम परीक्षा के भाव वाले प्रश्नपत्र

| | |
|---|---|
| प्रश्न पत्र (1) एडवांस्ड एकाउंटिंग | प्रश्न पत्र 1 एडवांस्ड एकाउंटिंग (ग्रुप 1) |
| प्रश्न पत्र (2) एडवांस्ड एकाउंटिंग एण्ड मैनेजमेंट एकाउंटिंग | प्रश्न पत्र 2 मैनेजमेंट एकाउंटिंग (ग्रुप 1) |
| प्रश्न पत्र (4) प्रोडिंटिंग | प्रश्न पत्र 3 प्रोडिंटिंग (ग्रुप 1) |
| प्रश्न पत्र (5) टैक्सेशन | प्रश्न पत्र 5 इरिक्ट टैक्स लाज (ग्रुप 2) |
| ग्रुप-2 | |
| प्रश्न पत्र (2) कम्पनी लाँ | प्रश्न पत्र 4 कम्पनी लाँ (ग्रुप 1)। |

सं० 1 सी० ए० (148)/85—चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट, 1949 (1949 का अड्रॉसबो) की धारा 30 की उप धारा (1) और (3) के अधीन प्रदान अधिकारों का उपयोग करते हुए, इन्स्टीट्यूट आफ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया की परिषद ने चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1984 में निम्नलिखित संशोधन किया है, इन संशोधनों को हमने भी प्रकाशित किया जा चुका है, तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त धारा को उपधारा (3) के अनुसार अनुमोदित किया जा चुका है।

कथित रेगुलेशन के सिक्कल "बीबी" में पैराग्राफ 14 के उप पैराग्राफ (1) की क्लॉज (सी) के अन्त में, निम्नलिखित को जोड़ दें:—
“(9)” बि इन्स्टीट्यूट आफ चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ बंगला देश।

मद्रास-600034, दिनांक 31 मार्च 1986

चाटर्ड एकाउन्टेन्ट्स

नं० 3-एस० सी० ए० (5)/13/85-86—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4-सी० ए० (1)/1069/70, दिनांक 3 सितम्बर, 1969, 4-एस० सी० ए० (1)/14/80-81 दिनांक 31 मार्च 1981, 4-एस० सी० ए० (1)/4/82-83 दिनांक 31 मार्च 1983, 3-एस० सी० ए० (4)/10/83-84 दिनांक 31 मार्च 1984, 3-एस० सी० ए० (4)/12/83-84 दिनांक 31 मार्च 1984 और 3-एस० सी० ए० (4)/7/85-86 दिनांक 30 सितम्बर 1985, के सन्दर्भ में चाटर्ड प्रा. लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसार एतद् तारायह सूचित किया

जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चाटर्ड प्रा. लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे की गई तिथि से स्थापित कर दिया है।

| क्र० सं० | सदस्यता सं० | नाम एवं पता | दिनांक |
|----------|-------------|---|-----------|
| 1. | 4367 | श्री जी० सुयानारायणा रमर्, ए० सी० ए०, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, 7-1-621/323, संजीवा रेड्डी नगर, हैदराबाद-500 038। | 17-2-1986 |
| 2. | 8423 | श्री एस० श्रीनिवासन, ए० सी० ए०, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, 106, पी० एस० के० नगर, कामाराजार डिस्ट० | 20-1-86 |
| 3. | 12939 | श्री एस० बेंकटारामन, ए० सी० ए०, 8, कामाधेनु, पेस्टम सागर, बम्बई-400089। | 18-2-86 |
| 4. | 18008 | श्री के० श्रीनिवासन, ए० सी० ए०, सी-74, बी० एच० ई० एल०, टाउनशिप, रानीपेट-632 406, नार्थ आर्कट डिस्ट०। | 12-2-86 |
| 5. | 19600 | मिसिज बाग्यालक्ष्मी शंकर, ए० सी० ए०, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट, नं० 22, वेस्ट रोड, वेस्ट सी० आई० टी० नगर, मद्रास-600 035। | 7-2-86 |
| 6. | 80253 | श्री एम० के० शाह, ए० सी० ए०, कोमिशियल मैनेजर, मेसर्स सुजाता टैक्सटाईल मिल्स, (प्रोप० भारत कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०), ननजान्गुड-571 301। | 2-2-86 |

नं० 3-ई० सी० ए० (5)/14/85-86—इस संस्थान की अधिसूचना नं० 4-ई० सी० ए० (II)/79-80 4-ई० सी० ए० (9)/81-82, 4-ई० सी० ए० (15)/81-82,

3-ई० सी० ए० (4)/11/82-83, दिनांक 15-3-80, 25-2-82, 23-2-82 और 31-3-83 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्ति लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्ति लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि से स्थगित कर दिया है।

| क्र० सं० | सदस्यता सं० | नाम एवं पता | दिनांक |
|----------|-------------|--|---------|
| 1. | 15760 | श्री समिरन घोष, ए० सी० ए०, 125, कालीबाड़ी रोड, न्यू बैरकपुर, 24, परगनास। | 10-2-86 |
| 2. | 50100 | श्री जी० हृदय चंघरी, ए० सी० ए०, 308-बी०, प्रिज अवर ग्राह रोड, कलकत्ता-700045। | 24-2-86 |
| 3. | 50193 | श्री अजय चौधरी, ए० सी० ए०, सोभियर एकाउन्टेन्ट, दि कलकत्ता इलेक्ट्रिक मण्डार्ड कॉर्पोरेशन लि०, विक्टोरिया हाऊस, कलकत्ता-700001। | 10-2-86 |
| 4. | 50538 | श्री वाई० पी० याम, थोमस ए० सी० ए०, स्यूट नं० 17, 512, बालमोरल एवेन्यू, विन्नीपेग, मनीटोबा, कनाडा आर० 3 बी०-2 पी० 8। | 14-1-86 |

आर० एल० चौधरी
सचिव

एअर इंडिया

एअर-इंडिया कर्मचारी आवास विनियम, 1967

सं० एच० क्यू०/58-5--वायुनिगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 45(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एअर-इंडिया एतद्द्वारा एअर-इंडिया कर्मचारी आवास विनियम, 1967 में संशोधन करने के लिए, नीचे लिखे अनुसार, आगे निम्नलिखित विनियम बनाती है:

1. (i) ये विनियम एअर-इंडिया कर्मचारी आवास (संशोधन) विनियम, 1985 कहे जा सकते हैं।

(ii) ये 1 जनवरी, 1986 से प्रभावी होंगे।

2. एअर-इंडिया कर्मचारी आवास विनियम, 1967 में विद्यमान विनियम 4(2) में, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा नामतः:

4. आवास गृह की स्थिति:

(2) आवास गृह के निर्माण या खरीद के लिए सामूहिक ऋण, भारत के भीतर भूमि या उसके भूखंडों की खरीद सहित, मंजूर किए जा सकते हैं, जहाँ निगम ने मार्गस्थ/मार्गबाह्य स्टेशन स्थापित किए हैं जिनमें उतंगर या उतंग विस्तार के भीतर का समावेश है जसा प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाए।

3. विद्यमान विनियम 5(3) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

5. ऋणों की मंजूरी के लिए सामान्य शर्तें

(3) इन विनियमों के अधीन उन मामलों में कोई ऋण मंजूर नहीं किया जाएगा, जहाँ कर्मचारी, उसका पति या उसकी पत्नी या उसकी किसी संतान के पास खुद का कोई मकान है, चाहे केवल उसी के नाम पर या एक-दूसरे के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से, लेकिन संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी इन शर्तों में तब ढील दे सकता है, जब वह संतुष्ट हो कि कर्मचारी के स्वामित्ववाला इस प्रकार का आवास सुविधाजनक या पर्याप्त नहीं है और कर्मचारी अपने सही आवासीय प्रयोजन के लिए एक अलग आवास बनाना या खरीदना चाहता है।

4. विद्यमान विनियम 9(1)(क) और 9(1)(ख) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

9. ऋण सीमाएं:

(1)(क) कोई भी व्यक्तिगत ऋण सामान्यतः ऋण के लिए कर्मचारी द्वारा ऋण के लिए आवेदन दिए जाने के समय उसके सांसारिक मूल वेतन और उसमें परिवर्ती मंहगाई भत्ते को जोड़ने पर उसके 75 गुना से या निर्माण की कुल लागत/तैयार निर्मित घर/फ्लैट्स की लागत (भूमि की लागत समेत) या 1,00,000 रुपये, इनमें से जो भी कम है, उससे ज्यादा नहीं होगा।

(1)(ख) जहाँ आवेदित व्यक्तिगत ऋण 1,00,000 रुपये से ज्यादा है, वहाँ अनुज्ञेय ऋण की राशि कर्मचारी द्वारा ऋण के लिए आवेदन दिये

जाने के समय उनके मासिक मूल वेतन और उसमें परिवर्ती मंहगाई भत्ते को जोड़ने पर उनके 60 गुना से या निर्माण की कुल लागत/तैयार निर्मित घर/फ्लैट की लागत (भूमि की लागत समेत) के 80 प्रतिशत (चार बटा पाँच) में से जो भी कम हो, उससे ज्यादा नहीं होगी, लेकिन यह राशि किसी एक मामले में अधिकतम 2 लाख रुपये ही हो सकती है।

5. विद्यमान विनियम 11 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

11. व्याज :

इन विनियमों के अधीन मंजूर किए गए प्रत्येक ऋण पर 5-1/2 प्रतिशत वार्षिक की दर से या उस संशोधित दर से जो निगम समय-समय पर विहित कर सकता है, साधारण व्याज लगेगा, परंतु, वैसे, यह कि जहां संबंधित कर्मचारी उन शर्तों को पूरा नहीं करता है जिनके अधीन ऋण मंजूर किया गया है या जहां, उन शर्तों को पूरा करने में अनावश्यक देरी होती है, जिसके लिए संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार हों, तो उन मामलों में, इन विनियमों के अधीन मंजूर किए गए ऋण पर, कर्मचारी द्वारा लिए गए पूरे ऋण के लिए विद्यमान बैंक दर से व्याज लगेगा। ऐसा सभी व्याज ऋणों के घटते हुए शेषों पर गिना जाएगा।

6. विद्यमान विनियम 12(1) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

12. प्रतिभूति :

- (1) व्याज सहित ऋण की वापसी एक विधिक बंधक द्वारा या जिस क्षेत्र में ऐसे बंधक की अनुमति हो वहाँ भूमि और मकान या फ्लैट के हक विलेख के जमा द्वारा बंधक के द्वारा रक्षित होगा, परन्तु यदि कर्मचारी व्याज सहित ऋण की पूरी राशि की वापसी को रक्षित करने के लिए समय-समय पर प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक को स्वीकार्य किसी अन्य प्रतिभूति की व्यवस्था करता है, तो प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक इस शर्त को छोड़ सकते हैं।

7. विद्यमान विनियम 14(2) और 14(8) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

14. आवास गृहों का निर्माण :

- (2) यदि ऋण सम्यक् रूप से मंजूर कर दिया जाता है, तो स्वीकृत ऋण के 35 प्रतिशत के बराबर की पहली किस्त कर्मचारी को उसके द्वारा निगम के पक्ष में भूमि और उस पर बनाये जाने वाले मकान का बंधक एक बंधक विलेख निष्पादित कर दिये जाने पर या निगम के पक्ष में हक

विलेखों को जमा करके बंधक या भार सृजित करने पर या कर्मचारी द्वारा विनियम 12 के उप-विनियम (1) के उपबंधों में यथा उल्लिखित अन्य प्रतिभूति दे दिये जाने पर, जैसी भी स्थिति हो चुका दी जाएगी।

- (8) स्वीकृत ऋण के 15 प्रतिशत के बराबर की दूसरी किस्त कर्मचारी को उनके द्वारा सिविल निर्माण एवं सम्पत्ति नियंत्रण या वित्त निदेशक को स्वीकार्य अन्य उपयुक्त एजेंसी से एक ऐसा प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करने पर चुकाई जाएगी कि मकान का निर्माण प्तिव्य स्तर तक पहुंच गया है।

8. विद्यमान विनियम 16(1) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

16. ऋण की वापसी :

- (1) ऋण का पूरा व्याज के साथ भाग पर प्रतिदेय होगा, किन्तु प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक कर्मचारी का व्याज सहित ऋण की वापसी ऐसी भाविक समान किस्तों में करने की स्वीकृति दे सकते हैं, जैसी प्रबंध निदेशक/उप प्रबंध निदेशक उचित समझे। ऐसी किस्तों का उचित बाद निर्धारित वापसी की शुरुआत की तारीख से अधिकतम बीस वर्षों की अवधि के दौरान चुकाई जा सकती है।

9. विद्यमान विनियम 19(1) के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

19. मकान का बिक्री या उठा लिया पर देना :

- (1) कर्मचारी, प्रबंध निदेशक को अभिव्यक्त लिखित सहमति के बिना, ऋण को उस पर व्याज के साथ पूरा-पूरा वापस कर देने से पहले ऋण को महापत्ता से उठाने द्वारा निम्न या खरीदे गए मकान को नहीं बेचेगा या किराए पर नहीं देगा। लेकिन, यदि किसी कारण से कर्मचारी ऋण को इस तरह वापस करने से पहले मकान बेचना चाहता है, या उठाने, या उसके हिस्से को किराए पर देना चाहता है, वह निगम को उसे खरीदने या उसे किराए पर लेने के लिए, जैसी भी स्थिति हो, बहुत बिलम्ब देने के लिए बाध्य होगा, परन्तु बस यह कि यदि कर्मचारी द्वारा दिया गया प्रस्ताव निगम द्वारा या किसी अन्य कर्मचारी द्वारा, उस प्रस्ताव की तारीख से तीस महीने के भीतर स्वीकार नहीं किया जाता है, तो वह प्रस्ताव जाएगा कि कर्मचारी का ऋण को महापत्ता से उठाने द्वारा बनाये गये या खरीदे गये मकान को बेचने या किराए

पर देने के लिए जरूरी सहमति प्रदान कर दी गई है।

10. विद्यमान विधियम 23 के लिए, निम्नलिखित विधियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:

23. व्याज :

प्रत्येक सामूहिक ऋण पर 5 1/2 प्रतिशत वार्षिक की दर से या उस संशोधित दर से जो निगम समय-समय पर विहित कर सकता है, साधारण व्याज लागेगा, परंतु, वैसे, यह कि जहां संबंधित सहकारी आवास समिति/या उसके संबंधित सदस्य उन शर्तों को पूरा नहीं करता है, जिनके अधीन ऋण मंजूर किया गया है या जहां उन शर्तों को पूरा करने में अभावश्यक देरी होती है, जिसके लिए संबंधित सहकारी आवास समिति/या उसके सदस्य जिम्मेदार हों, तो उक्त मामलों में, इन विधियों के अधीन मंजूर किए गए ऋण पर, सहकारी आवास समिति/या उसके सदस्यों द्वारा लिए गए पूरे ऋण के लिए विद्यमान बैंक दर से व्याज लागेगा। ऐसा सभी व्याज समय-समय पर अदत्त रहने वाले और न्यूनतम ऋणों के शेषों पर गिना जाएगा।

एम० नारायणस्वामी
सचिव

वर्ष 1983-84 के लिये दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

1. भूमिका

ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा इसके धर्मदा जिसे लोकप्रिय नाम "दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर" से जाना जाता है को उचित प्रशासन हेतु, वर्ष 1955 में संसद द्वारा "दरगाह ख्वाजा साहब अधिनियम" पारित किया गया था। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दरगाह के धर्मदा में सम्मिलित है :—

- (अ) दरगाह ख्वाजा साहब, अजमेर
- (ब) दरगाह शरीफ की सीमा में सभी इमारतें तथा चबूतरा सम्पत्ति।
- (स) दरगाह जागीर जिसमें दरगाह शरीफ से संबंधित सभी भूमि, भवन, दुकान तथा सभी अचल सम्पत्ति जहां भी स्थित हो, शामिल है।
- (द) अन्य सभी सम्पत्ति तथा सारी आय किसी भी स्रोत से दरगाह को समर्पित हो अथवा पाक अथवा खैराती उद्देश्यों के लिए दरगाह प्रशासन के अधीन रखी गई हो जिसमें अजमेर के होम-करम तथा किशनपुर गांवों की जागीरदारी सम्मिलित है।
- (ई) दरगाह की ओर से नाजिम अथवा अन्य व्यक्ति जो इसके द्वारा प्राधिकृत हो बाग्य प्राण सभी तज्जरातों तथा भेट की आय।

दरगाह के स्थायी आय के साधन का प्रशासन, नियंत्रण, तथा व्यवस्था दरगाह समिति अजमेर नामक समिति में निहित है। समिति में पांच से कम और दो से ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं जो सभी हफ्ते मुल्लाह तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे। समिति की राय से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नाजिम के लिए समिति अपने कार्य सम्पादन करती है। दरगाह प्रशासन का मुख्य अधिष्ठापी अधिकारी नाजिम होता है तथा यह समिति के सचिव की हैसियत से कार्य करता है।

इन अधिनियम की धारा 19 (1) के अधीन दरगाह के लेखों का प्रत्येक वर्ष ऐसे लोगों में, ऐसे ढंग से जैसा केन्द्रीय सरकार निर्देश दे, अपेक्षित है। इस अधिनियम की उप धारा (2) निर्धारित करती है कि समिति प्रत्येक वर्ष दरगाह के प्रशासन पर एक प्रतिवेदन तैयार करेगी जो लेखों तथा लेखों पर लेखा-परीक्षक के प्रतिवेदन के साथ सरकारी खातों में प्राप्ति होगी। दरगाह प्रशासन केवल प्राप्ति और भुगतान का एक विवरण तैयार करता है। तुलना पत्र तैयार नहीं किया जाता है और इस तरह लेखा अधि के अन्त में सम्पत्तियां तथा दायित्वों को लेखों से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।

प्रारम्भ में दरगाह के लेखों की लेखा-परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को सहमति आधार पर सौंपी गई थी। लेखे वर्ष 1978-79 से लेखा परीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षण (वर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के प्रावधानों के अधीन लाया गया।

2 प्राप्ति एवं भुगतान लेखा वर्ष 1983-84

2.1 प्राप्ति एवं भुगतान का विवरण

वर्ष के प्रारम्भ में प्रारम्भिक शेष 2.70 लाख रुपए था। वर्ष के दौरान कुल प्राप्ति 13.98 लाख रुपए थी (जिसमें 0.23 लाख रुपए के दान एवं मुआफिर खाता के निर्माण तथा दान पत्थरों की बचत तथा शौचालयों के निर्माण हेतु ऋण शामिल है)। वर्ष के दौरान कुल 15.64 लाख रुपए व्यय करने के उपरांत (जिसमें 4.14 लाख रुपए गौन भवन के ऊपर के कमरों के दरवाजे तथा कार्यालय कर्मों के निर्माण तथा लाईट अधिवृत्त का वेतन शामिल है) वर्ष के अन्त में अन्तिम शेष 1.04 लाख रुपए है उसमें से 0.02 लाख रुपए प्रामाणियों में विनियोजित है।

2.2 बिना अनुमान के अथवा अनुमान से अधिक व्यय किया गया।

दरगाह ख्वाजा साहब उप नियम 1958 के उपनियम 14 के अनुसार नाजिम को उपरोक्त उप नियम के नियम संख्या 22 के अन्तर्गत, पिछले वर्ष के समय किया गया वार्षिक आय-व्यय, पिछले वर्ष में वास्तव में

प्राप्त की गई अथवा व्यय को गई राशि और छूट वर्ष के लिए याभि बाद के वित्त वर्ष के आय व व्यय का मूल्यांकन का व्यौरा दर्शाते हुए छूट प्रस्ताव तैयार करना होता है और समिति के सदस्यों में प्रसारित करना होता है इन्हें समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और प्रति वर्ष मार्च में अनुमोदित किया जाता है।

वर्ष 1983-84 के लेखों के निरीक्षण से विदित हुआ है कि बिना आय व्ययक अनुमान के वार्षिक वर्षों के निर्माण पर 2.51 लाख रुपए व्यय किया गया और इफा-खाना (यूनानी) के वर्मचाणियों पर तथा साईट अभियन्ता के वेतन पर आय व्ययक अनुमान से अधिक व्यय किया गया। संगठन ने बताया (अप्रैल 1985) कि इस संबंध में समिति की कार्यवाही तत्काल ले ली जायेगी।

3. वार्षिक भूतियां (एन्यूटीज) बकाया रुपये 36,495.00

राशियां रुपये 32,861.00 (वार्षिक भूति राज-स्थान रुपये, 16,133.00 और वार्षिक भूति सबदड़ा रुपये 16,728.00) और रुपये 3,634.00 (मामूल शफा-खाना के लिये नकद अनुदान) क्रमशः राजस्थान सरकार तथा आंध्र प्रदेश सरकार से अवधि 1-1-1959 से 31-12-1983 की लम्बी अवधि से बकाया हैं। दरगाह प्रशासन ने बताया (अप्रैल 1985) किये पुराने मामले हैं और वसूली में समय लगेगा।

4. दरगाह सम्पत्तियों का बकाया किराया रुपये 80,849.51

दरगाह भवनों को विभिन्न किरायेदारों को किराये पर दिया गया। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार 15 अक्टूबर 1984 को, 31 मार्च 1984 तक की अवधि का कुल किराया रुपये 80,850.00 बकाया था --

| | मामलों की संख्या | बकाया राशि (रुपयों में) |
|--|------------------|-------------------------|
| (अ) विभिन्न न्यायालयों में लम्बित मामलों से सम्बन्धित बकाया किराया | 38 | 60,242 |
| (ब) दरगाह प्रशासन ने किराये की वसूली को आस्थगित रखा | 35 | 9,953 |
| (स) अन्य मामलों में बकाया किराया | 198 | 10,655 |
| | 271 | 80,850 |

किराया पंजीका की समीक्षा से यह भी विदित हुआ कि दरगाह भवन के एक हिस्से को 10 जुलाई 1974 से किराये पर दिया गया था किन्तु न तो किराये की राशि निश्चित की गई थी न ही गत दस वर्षों से वसूली की गई थी। इसके साथ ही दरगाह भवन का आधा हिस्सा किस तारीख से खाली

था, नहीं दर्शाया गया था। यह भी विदित हुआ कि दरगाह हवेली को किराये पर दिया गया था लेकिन सम्पूर्ण विवरण वसूली योग्य किराया, किराये पर देने की तारीख इत्यादि अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया था।

5. अन्य रोचक मामलों।

चल एवं अचल सम्पत्तियों के रजिस्टर में त्रुटियां।

दरगाह ख्वाजा साहब उप नियम 1958 के उप-नियम 21 के अनुसार दरगाह की अचल सम्पत्तियों की एक पुस्तक तथा चल सम्पत्तियों की सूची की एक पुस्तक बनाना अपेक्षित है। लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई कमियां नीचे दी जा रही हैं --

(I) अचल सम्पत्तियां।

अचल सम्पत्तियों के रजिस्टर के निरीक्षण से विदित होता है कि यद्यपि 395 सम्पत्तियों के विवरण को रजिस्टर में पूर्ण करने हेतु प्रविष्टियां की गई थी लेकिन सभी मामलों में क्षेत्र, निर्माण की लागत और भू सम्पत्तियों की क्रम संख्या आवंटित करने की प्रविष्टियों को पूर्ण नहीं किया गया था। कुछ मामलों में हाल ही में विखण्डित की गई और नव निर्मित सम्पत्तियों की प्राविष्टियां अभी भी पूर्ण करनी थी और इस आशय का प्रमाण-पत्र कि सभी अचल सम्पत्तियों की प्रविष्टियां रजिस्टर में कर ली गई हैं अभी रजिस्टर में दर्ज करना था।

(II) चल सम्पत्तियां।

गुम्बद शरीफ और मुख्य एवं सहायक तोशाखाना अन्तर्गत वस्तुएं।

गुम्बद शरीफ में कई सोने, चांदी तथा बहुमूल्य रत्न की कीमती वस्तुएं हैं लेकिन अभी तक इन सब वस्तुओं की सूची नहीं बनाई गई थी (नवम्बर 1984)

मुख्य तोशाखाना में भी सोने तथा चांदी की कीमती वस्तुएं हैं। तोशाखाना में (हफ्त चोकी बारीदारान) विभिन्न खादिमों के रात ताले हैं। तालों की चाबियां हफ्त चोकी बारीदारान के कमरों के पास होती हैं जो एक साफ एक ही समय में उपलब्ध नहीं होते हैं। तोशाखाना को खोलने तथा सूची बनाने हेतु दरगाह प्रशासन द्वारा वर्ष 1929 में एक प्रयास किया गया था लेकिन सफलता नहीं मिली थी अप्रैल 1966 में यद्यपि प्रशासन ने तोशाखाना खोला और 206 वस्तुओं की सूची बनाई लेकिन खादिमों के कथित अमहयोग के कारण यह कार्य पूरा नहीं किया जा सका।

अन्य सहायक तोशाखाना में कीमती गिलाफ (मकबरों की चद्दरे) सोने और चांदी की वस्तुएं इत्यादि हैं हालांकि मुख्य मकबरे पर गिलाफ (चद्दर) बदलने हेतु तोशाखाना प्रति दिन खोला जाता है फिर भी सहायक तोशाखाना की वस्तुओं की अभी तक सूची नहीं तैयार की गई है (नवम्बर 1985)

गुम्बद शरीफ एवं मुख्य तथा सहायक तोशाखाना की वस्तुओं की सूची को तैयार न करने का जिफ्र लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में वर्ष 1979-80 से लगातार किया जा रहा है दरगाह समिति की अगस्त 1982 और दिसम्बर 1982 में हुई सभाओं में गुम्बद शरीफ, मुख्य तोशाखाना व सहायक तोशाखाना की सूची तैयार करने का मामला रखा गया था लेकिन अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका अगस्त 1983 के दौरान सभा में यह निर्णय लिया गया था कि सभी सरगनाओं को गुम्बद शरीफ, मुख्य तोशाखाना और सहायक तोशाखाना की सम्पत्तियों की सूची बनाने एवं मूल्यांकन में सहयोग करने हेतु लिखित में कहा जाय और यदि व प्रत्युत्तर हीं देते हैं तो कानूनी कार्यवाही का सूत्रपात किया जाये परिणामस्वरूप एक के अलावा व सभी 9-11-1983 और 1-12-1983 को अजमेर में मिले और चांदी के कटहरे में की गई बघल के बारे में विचार विमर्श किया तत्पश्चात् सभा को किसी अन्य उपयुक्त तारीख के लिये स्थगित कर दिया गया अन्तिम निर्णय अब तक नहीं लिया गया है (अप्रैल 1985)

(6) माप पुस्तिका संख्या 4 का गुम होना ।

माप पुस्तिकाओं के निरीक्षण के दौरान यह सूचित किया गया था कि माप पुस्तिका संख्या 4 जो आधिशाषी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग को आंच हेतु भेजी गई थी, मार्ग में कहीं गुम हो गई थी और सभी प्रयासों के बावजूब इसे खोजा नहीं जा सका। चूंकि माप पुस्तिका एवं महत्वपूर्ण, तथा वास्तविक माप का अभिलेख है, माप पुस्तिका के गुम होने पर अपलिखित करने की दरगाह समिति की स्वीकृति नहीं ली गयी थी (अप्रैल 1985) ।

(7) विश्राम गृहों, सामूहिक शयनागार (डोरमिटरी)

इत्यादि का निर्माण अनियमितताएं तथा अधिक भूगतान 3.23 लाख रुपए ।

दरगाह विश्राम गृह समूह के निर्माण हेतु ठेकेदार को 3.23 लाख रुपय का अनियमित एवं अधिक भुगतान के बारे में दरगाह क्वाशा साहब अजमेर की वर्ष 1981-82 और 1982-83 की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में जिफ्र किया गया था। दिसम्बर 1983 में समिति की गत सभा में मामले पर पश्चात्ताप हुआ था और प्रस्ताव संख्या 16 के अनुसार समिति का यह मत था कि दरगाह एवं भवन निर्माण समिति की निगरानी की कमी के कारण अधिक भुगतान हुआ था। आगे यह भी निर्णय लिया गया था कि भविष्य में आर्थिक व्यय विवरण की दरगाह समिति द्वारा नियमित रूप से हर तिमाही जांच की जाये और वह समिति निर्माण कार्य पर किये गये व्यय के विवरण की गहनता से जांच करें। अधिक भुगतान की वसूली अभी भी की जानी थी (अप्रैल 1985) ।

8 गरीब नवाज विश्राम गृह समूह में पुराने कार्यालय व नागिम निवास गृह को विखण्डित करने में 13,750.00 रुपये का व्यय ।

इस कार्य के लिये तीन बार निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं। श्री अब्दुल कददार की 13750.80 रुपये की निविदा स्वीकृत की गई। श्री कददार को 13434.00 रुपये का भुगतान किया गया था व 316.00 रुपये का शेष कार्य विभाग द्वारा कराया गया था। इस संबंध में लिखी अनियमितताएं पाई गई थीं :—

(अ)—कार्य का मूल्य रुपये 5000.00 से अधिक का था लेकिन न तो जुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं न ही समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। संस्था ने बताया (अप्रैल 1985) कि इससे कार्य हल नहीं होता है क्योंकि जो लोग कार्य करते हैं वे सामाचार पत्रों को बिलकुल नहीं पढ़ते हैं।

(ब)—तुलनात्मक विवरण के अवलोकन से यह देखा गया था कि श्री के० के० भार्गव की निविदा दिनांक 17-8-1983 में बताई गई घरे सबसे कम थीं जो कि 11500.00 रुपये थी। संस्था ने बताया (अप्रैल 1985) कि उपर्युक्त ठेकेदार का प्रस्ताव झालरा में मलवा एवं पत्थर फैकने का था न कि अन्य किसी स्थान के लिये। फिर भी इसकी अस्वीकृति/जमायता के कारणों को दर्ज नहीं किया गया था।

9. परिहार्य व्यय एवं ठेकेदार को अनुचित वित्तीय सहायता (रुपये 38,935*00)

स्थानीय समाचार पत्र नव ज्योति दिनांक 18 नवम्बर 1982 द्वारा लंगर गेट दरगाह शरीफ के “नये विश्राम गृह” समूह के प्रवेश द्वारा” के निर्माण हेतु, जिसकी अनुमानित लागत एक लाख रुपय थी, मोहुरबन्द निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। लेकिन निविदाएं नहीं प्राप्त हुई थीं और “मूल अनुसूचित दर 1982” से 17 प्रतिशत ऊपर, मसल कमला इंजीनियरिंग कारपोरेशन, अजमेर को कार्य दे दिया गया था। अनुबन्ध के अनुसार दरगाह प्रशासन द्वारा निर्माण कार्य के लिय आवश्यक पानी, बिजली और इस्पात (केवल निर्माण खर्च देना था) मुफ्त देना था और सीमेन्ट 45.00 रुपये प्रति कट्टे की दर से देना था। गोल भवन के ऊपर के दो कमरों का अन्य निर्माण कार्य भी, समान दरों और भत्तों पर उसी ठेकेदार को दिया गया था इस सम्बन्ध में निम्नलिखित टिप्पणियां हैं —

(1) गोल भवन के ऊपर के दो कमरों का अनुमान नहीं तैयार किया गया था और दरगाह समिति से अनु-मोदित नहीं कराया गया था।

दरगाह प्रशासन ने बताया (अप्रैल 1985) कि निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि कार्य उसी ठेकेदार को दिया गया था जिसने उसी

अहाते के दरवाजे के निर्माण का कार्य किया था। मगर दरगाह का यह तर्क सही नहीं था।

समझौते के तहत दरगाह प्रशासन के द्वारा ठेकेदार को इस्पात की पूर्ति करना और निर्माण व्यय का भुगतान करना था। “मूल अनुसूचित दरों” के अनुसार निर्माण की दरें और ठेकेदार द्वारा ली गई दरें नीचे दिये अनुसार थीं—

अगर बिल्डिंग बायर ठेकेदार के थे तो उपयोग में लाये गये इस्पात की दर 70 पैसे प्रति किलोग्राम थी। अगर बिल्डिंग बायर दरगाह प्रशासन के थे तो उपयोग में लाये गये इस्पात की दर 50 पैसे प्रति किलोग्राम थी। 20 पैसे प्रति किलो ग्राम अन्तर की दर से दरगाह प्रशासन द्वारा दिये गये अन्तर को जो 1865-00 रुपये बनता है। (जो 7979 किलो ग्राम \times 20 पैसे प्रति किलो ग्राम रुपये 1594.00 + 17 प्रतिशत अधिमूल्य) को वसूल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ठेकेदार को 1752 रुपये का अधिक भुगतान किया गया था।

दरगाह प्रशासन ने कार्य के अनेक मदों में निर्देशन परिवर्तित किये थे जिसमें अतिरिक्त व्यय 24,736-00 रुपये का हुआ था। दरगाह प्रशासन ने सूचित किया था (अप्रैल 1985) कि ठेकेदार से राशि वसूल की

जायेगी। दरगाह समिति से इसको नियमित करने हेतु स्वीकृति नहीं ली गई थी (अप्रैल 1985)।

स्थान : जयपुर
दिनांक 4 जून 1985

(ह०) अपठनीय
महालेखाकार
(लेखा परीक्षा)
राजस्थान, जयपुर

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मने 31 मार्च 1984 को समाप्त होने वाले वर्ष के दरगाह खवाजा साहेब अजमेर के आय और व्यय लेखाओं की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं और संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अध्यधीन अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूं कि मेरी राय में और मेरी सर्वोत्तम सूचना और मुझे दिये गए स्पष्टीकरणों और संगठन की बहियों में किये गए उल्लेख के अनुसार ये लेखे उपयुक्त रूप से तैयार किये गए हैं और दरगाह खवाजा साहेब अजमेर के कार्यकलाप को सही और उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

स्थान : जयपुर
दिनांक 4 जून 1985

(ह०) अपठनीय
महालेखाकार
(लेखा परीक्षा)
राजस्थान, जयपुर।

STATE BANK OF PATIALA

HEAD OFFICE

Patiala-147 001, the 30th April 1986

NOTICE

No. Per/4869.—1. Shri K. R. Attri, Officer MMGS-II, has been transferred from Zonal Office, Chandigarh to GMO's Sectt., Head Office, Patiala and joined there on 18-2-1986.

2. Shri M. D. Singh, Officer SMGS-IV has been transferred from Patiala (Mall Road) Branch to Inspection Deptt., as Branch Inspector and joined there on 1-2-1986.

3. Shri B. Chaturvedi, Officer MMGS-II has been transferred from RM-II (Patiala) to Organisational & Planning Deptt. and joined there on 10-1-1986.

4. Shri R. K. Nangia, Officer MMGS-II, has been transferred from Staff Training Centre, Chandigarh to H.R.D. Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 29-1-1986.

5. Shri Rajinder Kumar Sharma, Officer MMGS-II has been transferred from New Delhi (Model Basti) to O & M Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 21-1-1986.

6. Shri Inderjit Singh, Officer JMGS-I has been transferred from RM-I (Patiala) to SIB Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 15-3-1986.

7. Shri M. K. Gupta, Officer SMGS-IV has been transferred from RM-I (Jalandhar) to SIB Deptt., Head Office, Patiala as Development Manager and joined there on 10-3-1986.

8. Shri Som Nath Arora, Officer JMGS-I, has been transferred from Dhamot to Lead Bank Deptt., as Associate Lead Bank Officer, Sangrur and joined there on 31-3-1986.

9. Shri B. L. Sharma, Officer, JMGS-I, has been transferred from Patiala (DCW) Branch to Balance Sheet and Govt. Accounts Section and joined there on 3-3-1986.

10. Shri V. K. Aggarwal, Officer JMGS-I, has been transferred from RM-II (Chandigarh) to Credit Appraisal Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 17-3-1986.

11. Shri H. S. Anand, Officer JMGS-I, has been transferred from CI & IB Deptt., to Credit Appraisal Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 10-3-1986.

12. Shri Mangoo Ram Goyal, Officer MMGS-II, has been transferred from Inspection Deptt. to Banking Operations Department, Head Office, Patiala and joined there on 4-3-1986.

13. Shri V. K. Gupta, Officer JMGS-I, has been transferred from Kalka Branch to Provident Fund Section, Head Office, Patiala and joined there on 31-3-1986.

14. Shri M. L. Gupta, Officer JMGS-I, has been transferred from Myserkhana to Central Accounts Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 7-2-1986.

15. Shri H. C. Singla, Officer MMGS-III, has been transferred from Patiala (Mall Road) Branch to S.T.C., Patiala as Chief Instructor and joined there on 29-1-1986.

16. Shri R. S. Atlas, Officer MMGS-II, has been transferred from Patiala (IA) Branch to Agriculture Deptt., Head Office, Patiala and joined there on 3-1-1986.

N. G. SARDANA
General Manager (Operations)

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the

186

No. N.15/13/7/12/82-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the

Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 16-4-1986 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Karnataka Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1958, shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Karnataka namely :—

| Name of the revenue Village | Hobli | Taluk | District |
|---------------------------------|----------|-----------------|-----------|
| 1. Arakere Village | Begur | Bangalore South | Bangalore |
| 2. Bommanahally | Do. | Bangalore South | Do. |
| 3. Konappana Agrahari Panchayat | Do. | Do. | Do. |
| 4. Hongasandra | Do. | Do. | Do. |
| 5. Bommasandra | Attibele | Anekal | Do. |
| 6. Madivala | Begur | Bangalore | Do. |
| 7. Hebbagodi | Attibele | Anekal | Do. |
| 8. Kudlu | Sarjapur | Anekal | Do. |

M. SUBBA RAO,
Director (Plg. & Dev.)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 28th April 1986

No. 28-RC(2)/23/86.—In pursuance of Regulation 136(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Southern India Regional Council at Pondicherry with effect from 3rd April, 1986.

The Branch shall be known as Pondicherry Branch of the Southern India Regional Council.

As prescribed under Regulation 136(3), the branch shall function subject to the Control, Supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

No. 28-RC(1)/12/86.—In pursuance of Regulation 136(1) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of the Western India Regional Council at Anand with effect from 3rd April, 1986.

The Branch shall be known as Anand Branch of the Western India Regional Council.

As prescribed under Regulation 136(3), the branch shall function subject to the Control, Supervision and direction of the Council through the Regional Council and shall carry out such directions as may from time to time be issued by the Council.

The 5th May 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 1-CA(131)/82.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has made the following amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, the same having been previously published and approved by the Central Government as required under sub-section (3) of the said section.

In the said Regulations, in Schedule 'B' after Paragraph 10, add the following new Paragraph 10A, namely :—

10A. Requirements for passing the Final Examination

(1) A candidate for the Final examination shall ordinarily be declared to have passed the examination if he passes in both the groups under sub-paragraph (1) of Paragraph 10 either taken simultaneously or at different examinations, securing a minimum of 40% of the marks in each paper of the group and a minimum of 50% of the total marks of all the papers of each group.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) above, a candidate who has passed in any one, but not both, of the groups at a Final examination under this Schedule held prior to 1st October, 1986 shall be entitled to exemption as indicated in column (2) of the table set out below as applicable in his case and shall be declared to have passed the Final examination if he secures the marks in the remaining paper or papers as specified in column (3) of the said table.

TABLE HEREINABOVE REFERRED TO

| Particulars of the Group passed by the candidate at the Final Examination under this Schedule held prior to 1st October, 1986 | Exemption to which the candidate is entitled at any Final examination held after 1st October, 1986 under Schedule 'BB' | The marks required to be obtained by the candidate in the non-exempted paper/s at the subsequent examination specified in column (2) hereof |
|---|--|--|
| Group I only | Papers 1, 2 and 3 of Group I & Paper 5 of Group II. | (i) Not less than 40% marks in Paper 4 of Group I, and (ii) Not less than 40% of the marks in each of papers 6, 7 and 8 of Group II and no less than 50% of the aggregate of the marks of the said papers 6, 7 and 8. |
| Group II only | Paper 4 of Group I. | (i) Not less than 40% of the marks in each of papers 1, 2 and 3 of Group I and not less than 50% of the aggregate of the marks of the said papers 1, 2 and 3, and (ii) Not less than 40% of the marks of each of the papers 5, 6, 7 and 8 of Group II and not less than 50% of the aggregate of the marks of the said papers 5, 6, 7 and 8. |

(3) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) above, a candidate who fails in one paper comprised in a group but secures a minimum of 60% of the total marks of the remaining papers of the Group shall be declared to have passed in that Group if he appears at any or more of the immediately next three following examinations in the papers in which he had failed and secures a minimum of 40% marks in that paper.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1) above, a candidate not covered by sub-paragraph (3), who fails in one or more papers, comprised in a group but secures a minimum of 60% marks in any paper or papers of that group and a minimum of 30% marks in each of the remaining papers of that group, shall be eligible to appear at any one or more of the immediately next three following examinations in the paper or papers in which he had secured less than 60% marks and shall be declared to have passed in that group if he secures at one attempt a minimum of 40% marks in each of such papers and a minimum of 50% of the total marks of all the papers of that group including the paper or papers in which he secured a minimum of 60% marks in the earlier examination referred to above.

(5) For the purpose of sub-paragraph (3) or sub-paragraph (4) thereof, the examination obtained in a paper or papers by a candidate in a Final examination held under sub-paragraph (1) of Paragraph 10 will continue to operate in relation to the Final examination under sub-paragraph (2) of Paragraph 9 of Schedule 'BB',

Explanation :

For the purposes of this sub-paragraph, the paper at which the candidate is required to appear as provided therein shall, in relation to a Final examination held under sub-paragraph (2) of Paragraph 9 of Schedule 'BB' mean the paper at such examinations which constitutes the corresponding paper as specified below and for the purpose of calculating 50% as specified in this paragraph, the Group shall mean the group under which the said corresponding paper or papers fall :—

| Paper at the Final examination under this Schedule held prior to 1st October, 1986. I | Corresponding paper under Schedule 'BB' at the Final examination held after 1st October, 1986. |
|---|--|
|---|--|

Group I

| | |
|---|---|
| Paper (1) : Advanced Accounting | Paper 1 : Advanced Accounting (Group I) |
| Paper (2) : Advanced Accounting & Management Accounting | Paper 2 : Management Accounting (Group I) |
| Paper (4) : Auditing | Paper 3 : Auditing (Group I) |
| Paper (5) : Taxation | Paper 5 : Direct Tax Laws (Group II) |

GROUP II

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Paper (2) : Company Law | Paper 4 : Company Law (Group I) |
|-------------------------|---------------------------------|

No. 1-CA(148)/85.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has made the following amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964, the same having been previously published and approved by the Central Government as required under sub-section (3) of the said section.

In the said Regulations, in Schedule 'BB', at the end of clause (c) of sub-paragraph (1) of paragraph 14, the following shall be added :—

"(9) The Institute of Chartered Accountants of Bangladesh".

R. L. CHOPRA,
Secretary

Madras, the 31st March 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

3SCA(5)/13/85-86.—With reference to this Institute's Notification Nos. 4CA(1)/10/69-70 dated 3rd September 1969, 4SCA(1)/14/80-81 dated 31st March 1981, 4SCA(1)/4/82-83 dated 31st March 1983, 3SCA(4)/10/83-84 dated 31st March 1984, 3SCA(4)/12/83-84 dated 31st March 1984 and 3SCA(4)/7/85-86 dated 30th September 1985, it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the following :—

| S. No. | M. No. | Name & Address | Date of Restoration |
|--------|--------|---|---------------------|
| 1. | 4367 | Shri G. Suryanarayana Sarma, A.C.A., Chartered Accountant 7-1-621/323 Sanjeeva Reddy Nagar Hyderabad-500038. | 17-02-1986 |
| 2. | 8423 | Shri S. Srinivasan, A.C.A., Chartered Accountant 106, P. S. K. Nagar Rajapalayam Kamarajar Distt. | 20-01-1986 |
| 3. | 12939 | Shri S. Venkataraman, FCA 8, Kamadhenu Pestom Sagar Bombay-400089. | 18-02-1986 |
| 4. | 18033 | Shri K. Srinivasan, A.C.A., C-74, BHEL Town Ship Ranipet-632406. North Arcot Distt. | 12-02-1986 |
| 5. | 19600 | Mrs. Bagyalakshmi Shankar, A.C.A., Chartered Accountant No. 22, West Road West CIT Nagar Madras-600035. | 07-02-1986 |
| 6. | 80253 | Shri M. K. Shah, A.C.A., Commercial Manager M/s. Sujata Textile Mills (Prop. Bharat Commerce & Industries Ltd.) Nanjangud 571301. | 02-02-1986 |

R. L. CHOPRA
Secretary

Calcutta-700071, the 31st March 1986

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 3ECA(5)(14)/85-86.—With reference to this Institute's Notification No./Nos. 4ESA/11/79-80, 4ECA/9/81-82, 4ECA/15/81-82 3ECA/4/11/82-83 dt. 15-3-80, 25-2-82, 23-2-82 & 31-3-83 it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members,

the names of the following members with effect from the dates mentioned against their names :—

| S. No. No. | Membership Number | Name & Address | Date |
|---------------|----------------------|--|---------|
| 1. | 15760 | Shri Samiran Ghosh, A.C.A., 125, Kalibari Road, New Barrackpore, 24 Parganas W.B. | 10-2-86 |
| 2. | 50100 | Shri G. Hazra Choudhury, A.C.A., 302B, Prince Anwar Shah Road, Calcutta-700045. | 24-2-86 |
| 3. | 50193 | Shri Anjan Chowdhuri, A.C.A., Sr. Accountant, The Calcutta Electric Supply Corporation Ltd., Victoria House, Calcutta-700001. | 10-2-86 |
| 4. | 50538 | Shri Y.P. Yam Thomas, A.C.A., Suite No. 17, 512, Balmoral Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada-R3B2P8 | 14-1-86 |

R. L. CHOPRA
Secretary

AIR-INDIA

Air India Staff Housing Regulations, 1967

No. HQ/58-5.—In exercise of the powers conferred by Section 45(i) of the Air Corporations Act, 1953 (27 of 1953), Air-India hereby makes the following regulations further to amend the Air-India Staff Housing Regulations 1967, as follows :

1. (i) These regulations may be called the Air-India Staff Housing (Amendment) Regulations, 1985;

(ii) They shall come into force from 1st January, 1986.

2. In the Air-India Staff Housing Regulations, 1967 for the existing Regulation 4(2), the following Regulation shall be substituted, namely :

4. Location of dwelling houses :

(2) Collective Loans may be granted for construction or purchase of dwelling house, including the purchase of land or plots thereof within India, where the Corporation has established online/offline stations including the suburbs or within such extensions as may be approved by the Managing Director/Dy. Managing Director.

3. For the existing Regulation 5(3), the following Regulation shall be substituted, namely :—

5. General condition for the grant of loans :

(3) No loan shall be granted under these Regulations in cases where the employees, his or her spouse or any of his or her children owns a house, whether individually or jointly with each other or with another person, but the sanctioning authority may relax this condition, if he is satisfied that the accommodation thus owned by the employee is not convenient or adequate and the employees desires to build or purchase a separate house for his or her bonafide residential purpose.

4. For the existing Regulation 9(1)(a) and 9(1)(b) the following Regulation shall be substituted, namely :—

9. Loan Limits :

(1) (a) No individual loan shall normally exceed 75 times the monthly basic pay plus Variable Dearness Allowance of the employee at the time he/she applies for the loan or the total cost of construction/cost of ready built house/flat (inclusive of the cost of land) or Rs. 1,00,000/- whichever is less.

(1) (b) Where the individual loan applied for is more than Rs. 1,00,000/- the amount of loan admissible shall not exceed 60 times the monthly basic pay plus Variable Dearness Allowance of the employee at the time he/she applies for the loan or 80% (four fifths) of the total cost of construction/cost of ready built house/flat (inclusive of the cost of land) whichever is less subject to a maximum of Rs. 2 lakhs, in any one case.

5. For the existing Regulation 11, the following Regulation shall be substituted, namely :—

11. Interest :

Every loan granted under these Regulations shall carry simple interest at the rate of 5½% per annum or such revised rate as the Corporation may prescribe from time to time provided, however, that where the employee concerned fails to fulfil the conditions under which loan has been granted or where undue delay, attributable to the employee concerned, is involved in fulfilling such conditions, the loan granted under these Regulations, in such cases, shall carry interest at the prevailing bank rate for full loan availed of by the employee. All such interest shall be calculated on the reducing balances of the loans.

6. For the existing Regulation 12(1) the following Regulation shall be substituted, namely :—

12. Security :

(1) The repayment of loan with interest shall be secured by a legal mortgage or by a mortgage by deposit of title deed of the land and house or flat in areas where such mortgage is permitted, provided that the Managing Director/Dy. Managing Director may waive this condition if the employee provides some other security acceptable to Managing Director/Dy. Managing Director from time to time to secure the repayment of the full amount of the loan with interest.

7. For the existing Regulation 14(2) and 14(8) the following Regulations shall be substituted, namely :—

14. Construction of dwelling houses :

(2) If the loan is duly sanctioned the first instalment equal to 35% of the sanctioned loan shall be paid to the employee upon his executing in favour of the Corporation a mortgage deed mortgaging the land alongwith the house to be built thereon or creating a charge or a mortgage by deposit of the title deeds in favour of the Corporation or on the employee furnishing other security as provided in the provisions to sub-regulations (1) of Regulation 12, as the case may be.

(8) The second instalment equal to 15% of the sanctioned loan shall be paid to the employee upon his/her producing a certificate from the Controller of Civil Works & Properties or other appropriate agency acceptable to the Director of Finance that the construction of the house has reached the plinth level.

8. For the existing Regulation 16(1) the following regulations shall be substituted, namely :

16. Repayment of loan :

(1) The loan together with interest thereon shall be repayable on demand, but the Managing Director/

Dy. Managing Director may permit an employee to repay the loan with interest in such monthly equated instalments as the Managing Director/Dy. Managing Director, may deem fit. Such instalments may be paid over a period not exceeding twenty years from date of commencement of repayment as hereinafter set forth.

9. For the existing Regulation 19(1) the following Regulation shall be substituted, namely :

19. *Sale or hire of house :*

- (1) The employee shall not, except with the express consent in writing of the Managing Director, sell or give on rent the house built or purchased by him with the assistance of the loan before the loan with interest thereon is repaid in full. If, however, for any reason, the employee desires to sell the house or to give it, or part thereof, on rent before the loan is so repaid, he shall be bound to give the Corporation the first option to purchase or to take it on rent, as the case may be, provided however, that if the offer made by the employee is not accepted by the Corporation or by any other employee, within three months from the date of such offer the employee shall be deemed to have been given necessary consent for selling or giving on rent the house built or purchased by him with the assistance of the loan.

10. For the existing Regulation 23, the following Regulation shall be substituted, namely :

23. *Interest :*

Every collective loan shall carry simply interest at the rate of 5½% per annum or such revised rate as the Corporation may prescribe from time to time, provided, however, that where the Co-operative Housing Society/or its members concerned fail to fulfil the conditions under which loan has been granted or where undue delay, attributable to the Co-operative Housing Society/or its members concerned, is involved in fulfilling such conditions, the loan granted under these Regulations, in such cases, shall carry interest at the prevailing bank rate for full loan availed of by the Co-operative Housing Society/or its members. All such interest shall be calculated on the balances of the loans for the time being and from time to time remaining unpaid.

S. NARAYANSWAMY
Secretary

Audit Report on Dargah Khwaja Sahib, Ajmer for 1983-84

1. Introductory :

For proper administration of Dargah and Endowment of the Khwaja Moinuddin Chisti popularly known as Dargah Khwaja Sahib, Ajmer the Dargah Khwaja Sahib Act was passed by the Parliament in 1955. As per provisions of the said Act, the Dargah Endowment includes :—

- (a) The Dargah Khwaja Sahib, Ajmer.
- (b) All buildings and movable property within boundaries of Dargah Sharif.
- (c) Dargah Jagir, including all land, houses and shops and all immovable property wherever situated belonging to the Dargah Sharif.
- (d) All other property and all income derived from any source whatever dedicated to the Dargah or placed for any religious, pious or charitable purposes under the Dargah Administration including the Jagirdari Villages of Hokram and Kishanpur in Ajmer.
- (e) All such nazars or offerings as are received on behalf of the Dargah by the Nazim or any other person authorised by him.

The administration, control and management of the Dargah Endowment is vested in a Committee named as "The Dargah

Committee Ajmer". The Committee is to consist of not less than five and not more than nine members, all of whom shall be Hanafi Muslims and shall be appointed by the Central Government. The Committee exercises its functions through Nazim appointed by the Central Government consultation with the Committee. The Nazim is the Chief Executive Officer of the Dargah Administration and also acts as a Secretary to the Committee.

Under Section 19(1) of the Act *ibid* the accounts of Dargah are required to be audited every year by such persons and in such a manner as the Central Government may direct. Sub Section (2) of the said Act envisages that the Committee shall every year prepare a report on the administration of the Dargah which together with the accounts and the report of the auditor thereon, shall be published in the Official Gazette. The Dargah administration is preparing only a statement of Receipts and Expenditure. No balance sheet is prepared and as such assets and liabilities at the end of the accounting period are not ascertainable from the accounts.

The audit of the Dargah was initially entrusted to the Comptroller and Auditor General of India on consent basis. From the accounts of the year 1978-79, the audit has been brought under the provisions of the Comptroller & Auditor General's (Duties & Powers and conditions of Service) Act, 1971.

2. Receipts & Expenditure Accounts for 1983-84

2.1 Analysis of receipts & expenditure

There was an opening balance of Rs. 2.70 lakhs at the beginning of the Year. The total receipts during the year amounted to Rs. 13.98 lakhs (including Rs. 0.23 lakh on account of donations and loan for construction of Musafir Khana, replacement of red stones and construction of latrines). After meeting the total expenditure of Rs. 15.64 lakhs during the year, (including Rs. 4.14 lakhs on construction of rooms, over gate building, construction of gate and office blocks and pay of Site Engineer, there is a closing balance of Rs. 1.04 lakhs at the end of the year out of which Rs. 0.02 lakh stands invested in securities.

2.2 Expenditure incurred without estimates or in excess of the estimates

According to Bye-law 14 of Dargah Khwaja Sahib Bye-Laws, 1958, the Nazim is to prepare and circulate among the members of the Dargah committee the budget proposal showing the amount budgeted for during the previous year, the amount actually received or spent in the previous year and the estimates of the income and expenditure for the budget year i.e. for the ensuing financial year as required under Bye-Law 22 *ibid*. These are placed before the Committee and approved in March every year.

A perusal of the accounts for the year 1983-84 has, however revealed that expenditure of Rs. 2.51 lakhs in respect of construction of Office blocks was incurred in the absence of budget estimates and in respect of Staff of Shafa Khana (Unani) and Pay of Site Engineer, expenditure incurred exceeded the budget estimates. The organisation stated (April 1985) that ex-post facto sanction of the committee would be taken.

3. Outstanding annuities Rs. 36,495/-

(i) Sums of Rs. 32,861/- (Annually, Rajasthan Rs. 16,133.00 and Annuity Sabdara Rs. 16728.00 and Rs. 3,634/- (Cash grant Mamool Sharma Khana) are outstanding against Government of Rajasthan and Government of Andhra Pradesh respectively for the period from 1-1-1959 to 31-12-1983 for a long time. It was stated by the Dargah Administration (April 1985) that these are old cases and will take time to realise.

4. Outstanding rent of Dargah properties Rs. 80,849.51 :—

A number of Dargah buildings were let out on rent to various tenants. Total rent outstanding for the period upto

31st March, 1984 as on 15th October, 1984 was Rs. 80,850/- as per details given be :

| | No. of cases | outstanding rupees |
|---|--------------|--------------------|
| (a) Rent outstanding in respect of cases pending in various courts. | 38 | 60242 |
| (b) Recovery of rent held in abeyance by Dargah Administration. | 35 | 9953 |
| (c) Rent outstanding in various cases | 198 | 10655 |

A review of the Rent register also revealed that neither the amount of rent has been fixed nor realised for the last ten years, for a portion of Dargah Bunglow rented out since 10th July, 1974. Further the date from which the half portion of Dargah Bunglow lying vacant, has not been indicated. It was also noticed that Dargah Haveli was let out but fully details viz. rent, recoverable date of letting out etc. were not found recorded.

5. Other topics of Interest

5.1 Defects in the Register of Immovable and Movable properties

According to Bye-Law 21 of the Dargah Khwaja Sahib Bye-Law 1958, a book detailing all immovable properties and a book containing a list of movable properties of the Dargah are required to be maintained. The deficiencies noticed in audit are mentioned below :—

(i) Immovable Properties

Examination of the Register of Immovable properties reveals that though entries have been made to complete the Register containing 394 properties, but entries regarding area, cost of construction and allotment of serial numbers to landed properties have not been completed in all the cases. In some cases entries of properties recently dismantled and those newly constructed are yet to be completed and a certificate to the effect that all the immovable properties have been entered in the Register is to be recorded in the Register.

(ii) Movable Properties

Articles under Gumbad Sharif and in Main and Subsidiary Toshakhana

There are many costly items of gold, silver and precious stones in the Gumbad Sharif but inventory of all these items has not been prepared so far (November, 1984).

The main Toshakhana also contains costly articles made of gold and silver. There are seven locks of different Khadims (Hafth Chowki Baridaran) on the Toshakhana. The Keys of the locks are with Sarganas of the Hafth Chowki Baridaran who were not available at one and the same time. Some time in the year 1929 an attempt was made by the Dargah Administration to open the Toshakhana and to prepare the inventory but without success. In April 1966 however the Administration got the Toshakhana opened and prepared a list of 206 items but the work could not be completed reportedly due to non-cooperation of the Khadims.

Another subsidiary Toshakhana contains costly Gijafs (Tomb covers) Silver and Gold articles etc. Even though the Toshakhana is opened almost daily for change of Gijafs on the Main Tomb, no list of articles in the Subsidiary Toshakhana has been prepared so far (November, 1984).

Non preparation of inventory of articles under Gumbad Sharif and in Main and Subsidiary Toshakhana has persistently been pointed out in the Audit Reports since 1979-80. The matter relating to preparation of list of Gumbad Sharif, Main Toshakhana and Subsidiary Toshakhanas was put up

before the Dargah Committee in their meetings held in August 1982 and December 1982 but no final decision could be taken. During August 1983 in a meeting it was decided that all the Sarganas may be asked in writing to cooperate in preparation of the inventory and valuation of the assets contained in Gumbad Sharif, Main, Toshakhana and Subsidiary Toshakhana and in case they do not respond legal action may be resorted to. As a result thereof the all excepting one met at Ajmer on 9-11-83, and on 1-12-1983 and discussed changes made in the silver katehra and thereafter postponed the meeting for some other suitable date. Final action has not so far been taken (April, 1985).

6. Loss of Measurement Book No. 4

During scrutiny of Measurement Books it was reported that Measurement Book No. 4 sent for check by the Executive Engineer Public Works Department was lost some where in transit and it could not be traced out inspite of all efforts. As Measurement Book is an important and initial record of actual measurement, the sanction of Dargah Committee for write off of the loss of Measurement Book was not obtained (April 1985).

7. Construction of Rest Houses, Dormitory etc. Irregularities and overpayment of Rs. 3.23 lakhs

Irregular and over payment of Rs. 3.23 lakhs to the contractor for construction of Dargah Rest Houses complex was pointed out in the Audit Report of Dargah Khwaja Sahib Ajmer for the year 1981-82 and 1982-83. The matter was discussed in the last meeting of the Committee held on December, 1983 and as per Resolution No. 16 the Committee was of the opinion that over payment was due to lack of supervision of the Dargah and Building Construction Committee. It was further decided that Income and Expenditure Statements should in future be checked quarterly by Dargah Committee regularly and that Committee should check thoroughly the Statements of expenditure on construction work. Recovery of overpayments made is yet to be effected (April 1985).

8. Expenditure of Rs. 13.750 incurred on dismantling of old office cum Nazim residence building in Garib Nawaz Guest House complex

Tenders for this purpose were invited thrice and tender of Shri Abdul Qaddar was accepted for Rs. 13750.00 and the remaining work for Rs. 316/-. Shri Qaddar was paid Rs. 13434/- was got done departmentally. The irregularities noticed are as under :—

(a) Value of the work exceeded Rs. 5000/- but neither open tenders were invited nor published in any news paper. The organisation stated (April 1985) that it did not serve the purpose because people who do such jobs do not read the papers at all.

(b) From the perusal of comparative statement it was noticed that rates quoted by Shri K. K. Bhargava in his tender dated 17-8-1983 were the lowest i.e. Rs. 11,500/-. The organisation stated (April 1985) that the offer of above contractor was for throwing debris and stone etc. at Jhaira and not for any other place. However, reasons for its non acceptance/rejection have not been found recorded.

9. Avoidable expenditure and undue financial aid to the contractor (Rs. 38.935)

Sealed tenders were invited for construction of "Entrance Gate of New Guest House complex" at Langar Gate Dargah Sharif (Estimate cost Rs. 1.00 lakh on 18-11-1982 through "Nav Jyoti" local daily News Paper. No tenders were received and work was awarded to M/s Kamla Engineering Corporation, Ajmer at 17% percent above basic scheduled rates 1982. As per agreement water & Electricity and Steel (only fabrication charges were to be paid) required for construction work were to be provided by Dargah administration free of cost and cement was to be provided at the rate of Rs. 45/- per bag. Another work of construction of two rooms on gale Building" was also awarded to the same con-

tractor on similar rates and conditions. The observations made are as under :—

- (i) Estimates for two rooms over the Gole Building were not prepared and got approved from the Dargah Committee.

The Dargah Administration stated (April, 1985) that there was no need of inviting tenders as the work was given to the same contractor, who had carried out the construction of gate within the same premises. The contention of Dargah is however not correct.

Under the agreement Dargah Administration was to supply steel to the contractor and fabrication charges were to be paid rates for fabrication as per basic scheduled rates and that charged by contractor are as under :—

70 paise per Kg. of steel consumed if building wire was of the contractor. 50 paise per Kg. of steel consumed if building wire was of the Dargah Administration.

The difference rate of 20 paise per Kg. paid by the Dargah Administration works out to Rs. 1865.00 (i.e. 7970 Kg. x 20 Paise per Kg. Rs. 1594+17% premium) has not been recovered. This has resulted into an overpayment out of Rs. 1752/- to the contractor.

The Dargah Administration has changed the specification in many items of work which involve extra expenditure of

Rs. 24,736.00. The Dargah Administration intimated (April 1985) that the amount would be recovered from the contractor. The sanction of Dargah Committee for regularisation of the same had not been obtained (April 1985).

AUDIT CERTIFICATE

I have examined the Receipt and Expenditure Account of Dargah Khwaja Sahib, Ajmer for the year ending 31st March 1984. I have obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of Dargah Khwaja Sahib, Ajmer, according to the best of information and explanation given to me and as shown by the books of the organisation.

Place : JAIPUR

Dated the 4th June 1985

Sd./- ILLEGIBLE
Accountant General (Audit)
Rajasthan, Jaipur